IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय ग्रामीण विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका

तहसीन फात्मा
शोध छात्रा
समाजशास्त्र विभाग
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर।

डा0 मोहम्मद रफीक
असि0प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
हलीम मुस्लिम पी0जी0कालेज कानपुर।

सारांश–

भारत में ग्रामीण विकास के संदर्भ में डिजिटल तकनीक एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है, जो ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली दीर्घकालिक चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करती है। यह सार कृषि उत्पादकता बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करने और उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में डिजिटल तकनीक की बहुमुखी भूमिका का पता लगाता है। मोबाइल तकनीक और इंटरनेट के एकीकरण ने मौसम के मिजाज, बाजार की कीमतों और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान की है, जिससे किसानों को सूचित निर्णय लेने में सशक्त बनाया गया है। ई–गवर्नेंस पहलों ने सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया है, नौकरशाही बाधाओं को कम किया है और लाभों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित की है। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने महिलाओं और हाशिए के समूहों के लिए रास्ते खोले हैं, आर्थिक क्षेत्र में समावेशिता और भागीदारी को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, इन तकनीकों के कार्यान्वयन में डिजिटल निरक्षरता, बुनियादी ढाँचे की कमी और सामाजिक–आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियाँ हैं। यह सार सतत ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता पर प्रकाश डालता है, साथ ही मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए लक्षित नीतियों और निवेश की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल प्रगति का लाभ ग्रामीण भारत के हर कोने तक पहुंचे।

मुख्य बिन्दु–

भारतीय ग्रामीण विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी।

परिचय

भारत में ग्रामीण विकास ऐतिहासिक रूप से गरीबी, शिक्षा तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और खराब बुनियादी ढाँचे जैसी चुनौतियों से घिरा रहा है। भारत की 65% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, इसलिए इन चुनौतियों का समाधान राष्ट्रीय विकास के लिए ज़रूरी है। हाल के वर्षों में, डिजिटल तकनीक ग्रामीण परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलावों को उत्प्रेरित करने में सक्षम एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के तेज़ी से प्रसार ने ग्रामीण समुदायों में नवाचार, सशक्तिकरण और विकास के लिए नए रास्ते खोले हैं। डिजिटल तकनीक किसानों को वास्तविक समय की जानकारी, उन्नत कृषि तकनीक और बाज़ार से जुड़ाव प्रदान करके कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को नया रूप दे रही है। यह बदलाव उत्पादकता और आय के स्तर को बढ़ा रहा है, जिससे ग्रामीण निवासी सूचित निर्णय लेने मंत सक्षम हो रहे हैं जो सीधे उनकी आजीविका को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, डिजिटल समाधान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार कर रहे हैं। ई–लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म भौगोलिक बाधाओं

को तोड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण छात्र गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों से जुड़ पा रहे हैं। टेलीमेडिसिन दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों के बीच की खाई को पाट रहा है, जिससे समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित हो रही है। हालाँकि, इन प्रगतियों के बावजूद, ग्रामीण विकास में डिजिटल तकनीक की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने की यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है। डिजिटल साक्षरता, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ जैसे मुद्दे व्यापक रूप से अपनाने और प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। यह परिचय भारतीय ग्रामीण विकास में डिजिटल तकनीक की भूमिका की गहन खोज के लिए मंच तैयार करता है, इसके लाभों, चुनौतियों और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक रणनीतियों की जाँच करता है।

कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी

कृषि, जो ग्रामीण आबादी के बहुमत के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। मोबाइल एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म किसानों को मौसम की स्थिति, मिट्टी की सेहत, कीट प्रबंधन और फसल की कीमत पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, किसान सुविधा और एग्रीऐप जैसे एप्लिकेशन किसानों को स्थानीयकृत जानकारी के साथ सशक्त बनाते हैं जो रोपण कार्यक्रम को अनुकूलित करने और नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सीधे बाजार तक पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। ड्रोन और प्वज उपकरणों सहित सटीक कृषि तकनीकों का उपयोग भी अधिक कुशल संसाधन प्रबंधन की अनुमति देता है। ये तकनीकें फसल के स्वास्थ्य की निगरानी और पानी और उर्वरकों के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करती हैं, जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ बनती हैं जो संसाधनों को संरक्षित करते हुए पैदावार में सुधार कर सकती हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में डिजिटल तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ई–लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन पाठ्यक्रम भौगोलिक बाधाओं के बावजूद छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। SWAYAM और DIKSHA जैसी पहल विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तक निःशुल्क पहुँच प्रदान करती हैं, जिससे शिक्षार्थी अपने भविष्य के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, टेलीमेडिसिन ग्रामीण आबादी के चिकित्सा सेवाओं तक पहुँचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। ई–संजीवनी जैसे प्लेटफ़ॉर्म रोगियों को स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से दूर से परामर्श करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे दूरी और परिवहन संबंधी चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक यह पहुँच उपचार में देरी को कम करती है और ग्रामीण समुदायों में समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती है।

ई–खेती :– आज ग्रामीणों व किसानों के पास सूचनाएं और नई–नई जानकारियां प्राप्त करने के कई माध्यम है परन्तु ग्रामीण विकास व कृषि से जुडी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ईटरनेट सबसे प्रभावी सरल व आसान माध्यम है। आज किसान देश के किसी भी कोने से ईमेल कर अपनी कृषि संबंधित किसी भी समस्या का हल कर सकते है। ई–खेती ने वैज्ञानिकों ने प्रसार कार्यकर्ताओं और विषय–वस्तु विशेषताओं पर ग्रामीणों की निर्भरता को बहुत ही कम कर दिया है। इंटरनेट के माध्यम से पलक झपकते ही सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते है ।

पूसा कृषि मोबाईल एपः – माननीय प्रधानमंत्री के प्रयोगशाला से खेत (लेब टू लैंड) तक के सपने को साकार करने के लिए पूसा कृषि मोबाईल एप किसानों की सहायता के लिए शुरू किया गया है।

एम किसान पोर्टल:– एम किसान पोर्टल कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा लाखों किसानों को परामर्श दिया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्वचालित मौसम केन्द्र जोडे गए हैं ।"

ई – पशुधन – हारपोर्टल की स्थापना :– देश में पहली बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवम्बर 2016 को मनाया गया। इसके शुभ अवसर पर राष्ट्रीय उत्पादकता मिशन के अंतर्गत ई– पशुधन – हार पोर्टल की शुरूआत की गई है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोडने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस पोर्टल के द्वारा किसानों को देशी नस्लों की नसलवार सूचना प्राप्त होगी। इससे किसान एंव प्रजनक देसी नस्ल की गाय भैंसों को खरीद एंव बेच सकेंगे।

वाई–फाई चौपाल : वर्ष 2016–17 में सीएससी एसपीबी ने ग्रामीण वाई–फाई चौपाल सुविधाए आरंभ की जिसके साथ ही गांवों में कनैक्टीविटी प्रदान करने के मामले में नया युग आ गया । वाई–फाई चौपाल परियोजनांए सीएससी के जरिए ग्रामीण भारत में वाई–फाई इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। पहली वाई–फाई चौपाल 07 अप्रैल 2016 को हरियाणा के फरीदाबाद में घरोंडा गांव में खोली गई। आज नो राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों की 819 ग्राम पंचायतों में वाई–फाई ढांचा स्थापित कर दिया गया है। 483 स्थानों पर इंटरनैट सेवा आरंभ हो चुकी है ।

डिजिटल साक्षरता अभियान :– इसके जरिए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के लक्ष्य की दिशा में बहुत उत्साह से काम किया। वर्ष 2016–17 में लगभग 35.44 लाख लोगों को इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणपत्र दिए गए। जिससे मार्च 2017 तक प्रमाण पत्र हासिल करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 56.46 लाख तक पंहुच गई। जो मार्च 2016 में मात्र 18.01 लाख ही थी । एनडीएलएम दिशा कार्यक्रमों के क्रियान्वतम में सफलता के कारण सीएससी, एसपीवी को डिजिटल साक्षरता के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 में आरंभ किए गए नए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) के क्रियान्वतम का जिम्मा भी दे दिया गया है।'

सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के इस विस्तार के फलस्वरूप गांवों में ई–क्रांति की लहर और तेजी से चलने लगी है गांवों के डाकघरों का भी कम्पयूटरीकरण किया जा रहा है। जिससे ये डाकघर बैंको की तरह साफ – सुथरे वातावरण में तेजी से काम करने वाले केन्द्र बन जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 को ई–प्रशासन वर्ष के रूप में मनाया। ई–प्रशासन के विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक अभिनव योजनाए चलाई गई है। जो स्थानीय स्तर पर उपयोगी भूमिका निभा रही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

1 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक योजना है, इसका उद्देश्य डिजिटल निरक्षरता के स्तर को कम करने के माध्यम से हाशिए के वर्गों सहित ग्रामीण आबादी को विशेष रूप से लक्षित करके डिजिटल विभाजन को पाटना है, जिससे छह करोड़ लोगों तक प्रभाव पड़ सके और लगभग 40% ग्रामीण घरों तक पहुंच हो, जिसमें कम से कम हर पात्र घर में एक सदस्य मार्च 2019 तक साक्षर हो। यह योजना नागरिकों को कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे डिजिटल एक्सेस उपकरणों को संचालित करने, ईमेल का उपयोग करने, डिजिटल भुगतान करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाती है।

ई–शक्ति

देश में सभी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड द्वारा 2015 में माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन विभाग के तहत एक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य देश के वित्तीय समावेशन एजेंडे के साथ सभी एसएचजी सदस्यों को एकीकृत करना है, ताकि एसएचजी सदस्यों और बैंकिंग सेवाओं के बीच तकनीकी रूप से गठबंधन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से उन्हें वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच मिल सके। वर्तमान में कुल बचत 1,932.09 करोड़ है, जो 4लाख से अधिक एसएचजी को कवर करती है।

इनाम

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत 14 अप्रैल 2016 को एक राष्ट्रीय कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार मंच के रूप में स्थापित किया गया, जो लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) द्वारा संचालित सभी नामांकित कृषि उपज विपणन समिति (APM) मंडियों को जोड़ता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक संघ बाज़ार का निर्माण करना है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मौजूद असममित जानकारी को मिटाता है, जिससे वास्तविक बाज़ार मूल्य के बारे में जागरूकता और कृषि नीलामी में पारदर्शिता की सुविधा मिलती है। वर्तमान में 80 लाख से अधिक पंजीकृत व्यापारी और 9.3 मिलियन पंजीकृत किसान हैं।

नाब कौशल

नाबार्ड ने नैबस्किल नामक एक डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित किया है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण चाहने वाले/प्रदाता और प्लेसमेंट एजेंसियों सहित अपने कौशल विकास पहलों में भाग लेने वाले हितधारकों का विवरण प्राप्त करना है। इसे 29 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था, यहाँ पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण संस्थान नाबार्ड से फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं।

ई–पंचायत

भारत भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई–गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ई–पंचायती मिशन परियोजना शुरू की है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन, सरकार और/या उसके विभागों की ज़रूरतें जिन्हें पंचायतों द्वारा पूरा किया जा सकता है, राज्य स्तरीय आईटी हस्तक्षेपों की प्रगति, आईसीटी के लिए पंचायतों की तत्परता। ई–पंचायत ग्रामीणों को एक एक्सप्रेस वेब–सक्षम प्रणाली के माध्यम से विवादों को निपटाने में सक्षम बनाता है, इसे ग्राम पंचायत में सभी सूचना और ज्ञान प्रबंधन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है।

हमें डिजिटल इंडिया की आवश्यकता क्यों है?

किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। अधिकांश सरकारी योजनाएँ खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण विफल हो जाती हैं। इसलिए, ग्रामीण भारत में सुचारू और तेज़ सेवा प्रदान करने के लिए, गाँवों को उचित संपर्क प्रदान करने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी के अलावा, जागरूकता और अनुप्रयोग ग्रामीण भारत में इंटरनेट की धीमी गति के मुख्य कारण हैं। हाई स्पीड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। मजबूत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल जमीनी स्तर तक कनेक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि तकनीक की मदद से उपकरण का उपयोग करने के लिए आत्मविश्वास और कौशल भी विकसित करता है। यह पहचानना बहुत बड़ी आवश्यकता है कि डिजिटलीकरण ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्देश्य प्राप्त किया है। निस्संदेह वस्तु के विषय पर पर्दे पर विभिन्न शोध हैं, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के पहलुओं और देहाती आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव को देखते हुए उद्धृत मामले पर कोई शोध नहीं हुआ है। इसलिए, यह विश्लेषण करने के लिए एक शोध की आवश्यकता थी कि डिजिटलीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक संरचना में भी प्रवेश किया है। प्रत्येक वर्ष सरकार गरीब लोगों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएँ शुरू करती है। उनमें से कुछ की निगरानी और उचित डेटा संग्रह की कमी के कारण विफल हो गए। हाल ही में सरकार ने मनरेगा की शुरुआत की है, जो पंजीकृत परिवारों को 100 दिनों के लिए एक दिन के लिए मांगने और प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। मनरेगा को समीक्षा के लिए अग्रणी कार्यक्रमों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है। चर्चा निस्संदेह है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के जीवन स्तर को बढ़ाएगा, बल्कि गरीबी उन्मूलन में भी मदद करेगा। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आईसीटी का उपयोग बढ़ाने, प्रसंस्करण लागत को कम करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आवश्यक है। हालाँकि, भारत ने सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन वयस्क साक्षरता दर बहुत खराब है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग एक–तिहाई भारतीय आबादी माध्यमिक शिक्षा में भाग नहीं लेती है, इसलिए यह आवश्यक है कि वयस्क आबादी के साथ डिजिटल इंडिया कितना कार्यात्मक निरक्षर है। तीसरी समस्या यह है कि अधिकतम जानकारी या इंटरनेट अंग्रेजी या हिंदी में है और क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत कम सामग्री उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण लोग अपनी स्थानीय भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं जो इंटरनेट में होना लगभग मुश्किल है। आखिरकार आजादी के सत्तर साल बहुत दूर नहीं हैं और कई गाँव बिना बिजली के बिजली का उपयोग कैसे करते हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल तकनीक ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास में लगातार चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करती है। सूचना अंतराल को पाटने और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाकर, डिजिटल उपकरण ग्रामीण निवासियों के जीवन को बदल रहे हैं और सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और बेहतर शैक्षिक अवसरों की संभावना दर्शाती है कि प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण चालक हो सकती है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए डिजिटल अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने के लिए एक ठोस

प्रयास की आवश्यकता है। प्रयासों को डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने और सामाजिक–आर्थिक समूहों में प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नीति निर्माताओं, सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज को एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए जो ग्रामीण समुदायों को प्रौद्योगिकी के लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे–जैसे भारत अधिक डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, ग्रामीण विकास रणनीतियों में डिजिटल समाधानों को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण होगी। इस परिवर्तनकारी क्षमता को अपनाकर, भारत गरीबी को कम करने, आजीविका बढ़ाने और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। अंततः, एक व्यापक दृष्टिकोण जो प्रौद्योगिकी को सामुदायिक सहभागिता और क्षमता निर्माण के साथ जोड़ता है, वह अधिक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण कर सकता है।

संदर्भ (reference)

[1] सेतिया सुभाष (जनवरी 2012) – गावों में सूचना प्रौद्योगिकी का बढता प्रभाव कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, अंक 03 पृ0 22

[2] कुमार विरेन्द्र (अगस्त 2017), ई – तकनीकी का ग्रामीण विकास में योगदान कुरूक्षेत्र सूचना प्रशासन मंत्रालय नई दिल्ली, अंक 10, पृ0 41

[3] मितल संजीव (अगस्त 2017), कुरूक्षेत्र सूचना प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 10, पृ0 12

[4] सिंह, नीना (2007) "भारत में डिजिटल विभाजन को पाटनारू चुनौतियाँ और अवसर", विश्व पुस्तकालय, खंड 17, संख्या1.

[5] शीतल टी. एवं जी. कृष्णमूर्ति (2017) कैशलेस ग्रामीण अर्थव्यवस्था – एक सपना या हकीकत? झारखंड जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज एक्स.आई.एस.एस., रांची, खंड 15, संख्या 2, पृ. 7269–7281

[6] लोकेश्वरी और ऐश्वर्या (2017) जर्नल ऑफ कंटेंट, कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन, वॉल्यूम 6, आईएसएसएन: 2395–7514

[7] योति यादव (2015) डिजिटल इंडियारू ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक रोडमैप, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिसर्च, आईएसएसएनरू 2455–1627, खंड 1 (अंक 2 (पृष्ठ संख्या 77–80

[8] तुकेश एट अल (2017) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट, आईएसएसएनरू 2348–6406, डीओआई: 10.21090।

[9] भाटिया, ए., और किरण, सी. (2016)। भारत में ई–गवर्नेंस पहल के माध्यम से ग्रामीण विकास। आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (आईओएसआर–जेबीएम), एसआई, 61–68

[10] जिंदल एस. और ओझा बनाम (2017) ई–पंचायतरू एक क्रांति, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, खंड 6. अंक 02.